भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 603

उत्तर देने की तारीख 04 फरवरी, 2026

बुधवार, 15 माघ, 1947 (शक)

भारत के कार्यबल में शिक्षा का निम्न स्तर

603. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के लगभग 73 प्रतिशत कार्यबल को केवल मूलभूत शिक्षा प्राप्त है, और लगभग 47 प्रतिशत कार्यबल प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाया है, जैसा कि मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में रेखांकित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस शैक्षिक अंतर के कारण, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों, में श्रम उत्पादकता में कमी और कौशल असंगतियां पैदा हुई हैं; और

(ग) भारत के लिए वर्ष 2030 के आसपास अनुमानित कार्यबल की उच्चतम वृद्धि से पहले कार्यबल की शिक्षा और कौशल स्तरों को बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट और समयबद्ध उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के नवीनतम वार्षिक अनुमानों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 72.9 प्रतिशत व्यक्तियों ने माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। साथ ही, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 41.0 प्रतिशत व्यक्तियों ने माध्यमिक और उससे उच्च स्तर की शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सकल नामांकन दर (जीईआर) 68.5 प्रतिशत है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) वर्ष 2021-22 के अनुमानों के अनुसार, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सकल नामांकन दर (जीईआर) 28.4 प्रतिशत है।

किसी देश की उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर वेतनभोगी एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयासों में शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रोजगार के अवसरों (वेतनभोगी या स्वरोजगार) को बढ़ाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने कार्यबल की शिक्षा और कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) वर्ष 2018-19 से, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 'समग्र शिक्षा' योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा प्राप्त हो। पीएम-ईविद्या देश भर में शिक्षा तक बहुमोड़(मल्टी-मोड) पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) राष्ट्र का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री के साथ-साथ सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड युक्त एनर्जाइड टेक्स्ट्बुक्स(ईटीबी) उपलब्ध कराता है।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, सरकार ने उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 2035 तक 26.3% से बढ़ाकर 50% करने की योजना बनाई है। उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या वर्ष 2018-19 में 51,649 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 58,643 (अनंतिम) हो गई है। छात्रों की संख्या वर्ष 2018-19 में 3.74 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4.46 करोड़ (अस्थायी) हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2020 में 7 से बढ़कर वर्ष 2025 में 123 हो गई है। इसके अलावा, भारत में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में नए संस्थानों का निर्माण और मौजूदा संस्थानों का उन्नयन करके बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, छात्रवृत्ति और वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय सहायता बढ़ाना और स्वयं (स्टेडी वेब्स ऑफ एक्टिव -लर्निंग फॉर यंग एसपिरिंग माइंडस) और एनपीटीईएल (नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नालजी एनहैन्स्ड लर्निंग) जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है।

(iii) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अधीन, विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा इस प्रकार है:

योजना का नाम	**समग्र**
पीएमकेवीवाई	1,64,34,210
(वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.12.2025 तक)	34,14,181
जेएसएस	47,19,923
(वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.12.2025 तक)	1,07,42,151

(iv) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने एसआईडीएच (सिद्ध) को एक एकीकृत मंच के रूप में लॉन्च किया है जो कौशलीकरण विकास, शिक्षा और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को एकीकृत करता है और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करते हुए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, का ब्यौरा एसआईडीएच (सिद्ध) पोर्टल पर उपलब्ध है ताकि वे संभावित नौकरियों और शिक्षुता के अवसरों से जुड़ सकें। भारतस्किल्स पोर्टल 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध ई-पुस्तकों, प्रश्न बैंकों और ई-लर्निंग वीडियो सहित विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करके कौशल विकास में सहायता करता है।

(v) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षण संस्थानों में मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के एकीकरण पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (एनसीआरएफ) प्रारंभिक, स्कूली, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को समाहित करने वाले एक व्यापक क्रेडिट संचय एवं हस्तांतरण ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यधारा की शिक्षा के साथ स्वतंत्र या एकीकृत कार्यक्रमों के रूप में प्रदान किए जाते हैं। स्नातकों की रोजगार क्षमता और दक्षताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा शिक्षुता आधारित डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम भी प्रदान किए जाते हैं।

*****